भारत - नेपाल संबंध – आगे कैसे बढ़े?

संदर्भ

- पछिले कुछ समय से नेपाल के आंतरकि मामलों के कारण भारत – नेपाल सीमा कई दनिों तक अवरुद्ध रही, जसिके कारण नेपाल ने अपनी कुछ महत्त्वपूर्ण सीमा चौकयिों पर भारत द्वारा आर्थकि नाकेबंदी का आरोप लगाया। यद्दपभिारत ने नेपाल के इस आरोप को खारज़ि कर दयिा परन्तु नेपाली मधेसी समुदायों की कुछ चतिाओं के प्रतभिारत की सहानुभूतभिी कसिी से छपिी नहीं है। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट देखने को मलिी, जसिका लाभ उठाने में चीन भला क्यों पीछे रहता।
- इस आलेख में आर्थकि प्रतबिंध को लेकर भारत की क्या नीतरिही है एवं आगे क्या होना चाहयि, तथा भारत-नेपाल संबंधों के लयि आगे क्या रास्ता हो, इसकी चर्चा की गई है।

वश्लिेषण

- भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध माना जाता है। बहिार और पूर्वी-उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतकि एवं नृजातीय संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई वशिेष प्रतबिंध नहीं रहा। सामाजकि और आर्थकि वनिमिय बनिा कसिी गतरिोध के चलता रहता है।
- परन्तु पछिले कुछ वर्षों में नेपाल की आंतरकि राजनीतकि उठा-पटक के कारण दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट दखिी है। भारत पर उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहा है। मधेसी समुदायों ने अपनी कुछ मांगों के न सुने जाने के कारण भारत–नेपाल सीमा पर कई दनिों तक परविहन अवरुद्ध कर दयिा था। नेपाल ने इसे भारत द्वारा आर्थकि नाकेबंदी करार दयिा।
- नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खडग प्रसाद शर्मा ओली ने भारत पर नेपाल की सीमा के कुछ महत्त्वपूर्ण रास्तों के नाकाबंदी करने का आरोप लगाया था। भारत ने इस आरोप का खंडन कयिा है।
- हालाँकयिह बात भी वचिारणीय है कमिधेसयिों के प्रतसिहानुभूतरिखने तथा नेपाल सरकार को उनकी समस्याओं को दूर करने की सलाह देने वाला भारत इस मुद्दे की अनदेखी कैसे कर सकता है। बनिा कसिी समर्थन के इतना बड़ा परविहन गतरिोध तथा वह भी लम्बे समय तक भला कैसे चल सकता है ? नेपाल ने इस वषिय को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया था।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पश्चमिी देशों के आर्थकि बल प्रयोग का भारत भले ही वरिोध करता हो, परन्तु बीते समय में नई दल्लिी ने अपने राजनीतकि उद्देश्यों की पूर्तकि लयि इस अस्त्र का बखूबी प्रयोग कयिा है। अपने राजनीतकि उद्देश्यों की पूर्तकि लयि भारत कसि तरह आर्थकि दबाव का सामरकि प्रयोग करता है, नेपाल की नाकेबंदी इसका एक उदाहरण है।
- भारत द्वारा घाटबंधी, आर्थकि नाकेबंदी तथा वत्तिीय प्रतबिंध जैसे आर्थकि उपकरणों के उपयोग का यह पहला उदाहरण नहीं है। भारत अपने हतिों की पूर्तकि लयि बीते समय में अन्य देशों में भी इनका प्रयोग कर चुका है। नेपाल, पाकसि्तान तथा दक्षणि अफ्रीका इसके महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।
- हालाँककिुछ अवसर ऐसे भी आए हैं जब भारत ने न केवल आर्थकि दबाव के उपयोग करने की घोषणा की है बल्कइिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लयि पैरवी भी की है।
- भारत ने दक्षणि अफ्रीका के वरिुद्ध वर्ष1946 से 1993 तक आर्थकि दबाव का उपयोग कयिा था जब भारत ने पाया कभिारतीय डायस्पोरा के प्रत वहाँ की सरकार का व्यवहार भेदभावपूर्ण एवं हानकिारक है।
- इसी प्रकार वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के पश्चात,भारत ने पाकसि्तान से संचालति जैश-ए-मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैएबा को इस हमले के लयि ज़म्मिेवार ठहराते हुए पाकसि्तान पर प्रतबिंध लगा दयिा था, जसिका आर्थकि प्रभाव पड़ा था।

भारत का दृष्टकिोण

- कई पश्चमिी देशों के नेताओं ने यहाँ तक की ईरान एवं ब्राज़ील जैसी उभरती हुई शक्तयिों ने भी आर्थकि बल प्रयोग के प्रतअिपने दृष्टकिोण को स्पष्ट कर रखा है। वहीं भारतीय नेताओं ने इस वषिय पर प्राय: बच नकिलने का प्रयास कयिा है। हालाँकविदिेश नीतप्रितष्ठिानों में यह कसिी से छपिा नहीं है कभिारत इस नीतकिा उपयोग नहीं करता। इसके अतरिक्ति जब भी पश्चमिी देशों द्वारा इसके लगाए जाने की बात आई है तो भारतीय अधकिारीगणों ने इसकी केवल चर्चा भर की है।
- पछिले कुछ वर्षों से भारत ने व्यक्तगित तौर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ईरान एवं रूस के वरिुद्ध एकतरफा आर्थकि प्रतबिंध लगाए जाने पर कड़ा रूख अपनाया है। नई दल्लिी का मानना है कएिकतरफा आर्थकि प्रतबिंध से वैश्वकि अर्थव्यवस्था प्रभावति होती है। इसलयि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतबिंधों का समर्थन कयिा है न कएिकतरफा प्रतबिंधों का।
- चीन की तरह भारत ने भी आर्थकि बल प्रयोग के उपायों को वैधानकि या स्पष्ट वनियिमन के माध्यम से औपचारकि नहीं बनाया है, जैसा कअिमेरकिा तथा यूरोपीय संघ ने कयिा है।

सावधानी

- अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकवील के अनुसार अमेरिका भारत के साथ मिलकर आर्थिक कूटनीति के इस उपकरण को और मज़बूत बनाना चाहता है।
- भारत को अमेरिकी सलाह पर कार्य करने से पहले सावधान रहना होगा। पश्चिमी देशों द्वारा अब तक लगाए गए आर्थिक बल प्रयोगों की सफलता-असफलता तथा उसकी मानवीय लागत पर विचार करने के बाद ही भारत को इस सलाह को मानना चाहिये या इस पर आगे बढ़ना चाहिये।
- भारत को आर्थिक दबाव का प्रयोग करने से पहले निम्न तीन कारकों पर विचार करना चाहिये-

प्रथम- ऐसा करते समय अन्य कोई हानि कम-से-कम हो।
दूसरा- इसके प्रभावी उपयोग के लिये भारत को उस देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझना चाहिये। जैसे नेपाल पर प्रतिबंध लगाने से वह चीन की ओर झुक सकता है।
तीसरा- इस कार्य की लागत पर विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि प्रतिबंध लगाने वाला राज्य उस देश में मौद्रिक लागत के साथ-साथ अपनी प्रतिष्ठा भी खो सकता है, जैसा कि भारत और नेपाल के मामले में देखा गया है। इस तरह से प्रतिष्ठा की हानि को कूटनीतिक उपाय से जल्दी भरा नहीं जा सकता है।

निष्कर्ष
यद्यपि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का पिछला कार्यकाल दोनों देशों के संबंधों के लिये उत्पादक रहा, फिर भी भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन से पहले रणनीतिक लाभ–हानि पर विचार अवश्य कर लेना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-nepal-relations-1